भण्डू, कान्हा, भोपाल-सांची, पचमढ़ी और उज्जैन, और राजस्थान में अम्बेर, जैसलमेर, हल्दीघाटी और महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित चार अन्य स्थान हैं। योजनाओं का ब्यौरा और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये दी जाने वाली सापेक्ष प्राथमिकताओं का निर्णय, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यटन और नागर विमानन मंत्री की अध्यक्षता में शीघ्र ही बुलायी जाने वाली एक बैठक में लिया जायेगा।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे विकास हेतु प्रस्तावित पर्यटक केन्द्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर लें, यथा :

(i) वे केन्द्र, जो केवल स्थानीय महत्व के हैं।

(ii) वे केन्द्र, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जहां मुख्यत: स्वदेशी पर्यटक ही आते हैं।

(iii) वे केन्द्र, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के हैं।

यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि श्रेणी (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों का ही होगा, जब कि श्रेणी (iii) में शामिल पर्यटक केन्द्रों के विकास का संपूर्ण दायित्व केन्द्रीय सरकार का होगा।

Decision to allow Actual Users to Import Soda Ash

2982. SHRI KUSMA KRISHNA MURTHY: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to allow actual users to import soda ash directly against firm contracts entered into with overseas suppliers before August 1, 1978;

(b) if is, the number of such contracts entered into by the actual users and the amount of soda ash imported by them against such contracts; and

(c) to what extent the demand of soda ash is likely to be met by such import?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.

(b) According to the information available, thirteen firms have imported or have been granted import licences for a total quantity of about 15,750 metric tonnes, and import applications from ten firms covering a quantity of 6,650 metric tonnes are pending.

(c) The estimated gap between indigenous production of soda ash and demand for the item is about 50,000 tonnes, against the figure of 22,400 tonnes that would be available through commitments made before 1-8-1978.

Representation made by State Governments regarding Report of Seventh Finance Commission

2983. PROF. P. G. MAVALANKAR. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether one or more State Governments have reacted to and repre-